THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Suggestions offered by rites to planning Commission for implementation of log book system for

Estimation of traffic data

3574. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Rail India Technical and Economic Services (RITES) has suggested to the planning Commission for log books system at a grassroot level for proper accounting of traffic data in the country;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) to what extent the data collection would help in finding out the actual demand of vehicles light, medium and heavy traffic load on the roads;

(d) whether similar data has been collected earlier by RITES in 1986-87;

(e) if so, what are its details;

(f) what steps the Planning Commission have taken or propose to take for the collection of data about traffic load on the roads in the country; and

(g) what are the details of statistics available with the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) RITES had requested the Planning Commission to be given a contract for undertaking a Study of commodity flows based on data available on such log books maintained by State Governments under the Motor Vehicles Act, 1988.

(c) As all the State Governments have not yet framed these rules, compilation of data and a study based on trucks, documents on all India basis would not be possible. Origin and destination flows by themselves would not help in determining the future demand of vehicles by types.

(d) and (e) In 1986-87, RITES conducted an All-India sample survey of freight traffic based on information gathered from truck operators, in connection with the work of the Steering Committee on Perspective Planning for Transport Development constituted by the Planning Commission.

(f) Planning Commission have suggested that relevant provisions of the Motor Vehicles Act should be implemented by all States. Commodity flows and other relevant traffic data could then be obtained on the basis of scientific sample surveys.

(g) The estimates of traffic carried by road, and other modes, as also the results of the 1986-87 surveys of origin and destination, commodity flows conducted by RITES are available with Government.

केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित मानदण्ड

3575. **श्री राजूभाई ए० परमार:** क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त मानदण्डों का पालन करने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं ; और

(ग) गत वर्ष उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संशोधित गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत निर्धारित मान दस अक्टूबर, 1990 में यथा संशोधित फार्मूला और दिसम्बर, 1991 में यथा संशोधित फार्मूला सलग्न विवरण–I **(नीचे देखिये)** में दर्शाए गए हैं ।

(ख) जी , नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अक्टूबर, 1990 में संशोधित किए गए फार्मूले के अनुसार 1991-92 के दौरान किए गए केंद्रीय सहायता (सकल) के राज्यवार आवंटन विवरण II में (नीचे देखिए) दिए गए हैं ?।

विवरण–I

राज्यों को योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में आवंटन के लिए संशोधित गाडगिल फार्मूला और अक्तूबर, 1990 और दिसम्बर, 1991 में यथा संशोधित फार्मूले के अधीन मानदंड और अधिभार

(अधिभार प्रतिशत)

मानदंड	संशोधित गाडगिल फार्मूला (1980)	राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा संशोधित फार्मूला (1990)	राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा संशोधित (1991)
क. विशेष श्रेणी के राज्य (10)	उत्तर पूर्वी परिषद् को छोड़कर 10 राज्यों का 30% हिस्सा	उत्तर पूर्वी परिषद् सहित 10 रज्यों का 30% हिस्सा	उत्तर पूर्वी परिषद् को छोड़कर 10 राज्यों का 30% हिस्सा
ख. गैर-विशेष श्रेणी के राज्य (15)			
(i) **जनसंख्या** (1971)	60.0	55.0	60.0
(ii) **प्रति व्यक्ति आय** जिसमें से	20.0	25.0	25.0
क) केवल राष्ट्रीय औसत से निचे की प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को शामिल करते हुए "विचलन' पद्धति के अनुसार	20.0	20.0	20.0
(ख) सभी पन्द्रह राज्यों को शामिल करते हुए "अंतर" पद्धति के अनुसार	—	5.0	5.0

1	2	3	4
(iii) **कार्य निष्पादन** जिसमें से	10.0	5.0	7.5
(क) कर प्रयास	10.0	—	2.5
(ख) वित्तीय प्रबंध	—	5.0	2.5
(ग) राष्ट्रीय उद्देश्य	—	—	2.5
(घ) विशेष समस्याएं	10.0	15.0	7.5
जोड़	100.0	100.0	100.0

टिप्पणी :

1. वित्तीय प्रबंध का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों को लेते हुए वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय अनुमानित किए गए राज्यों के स्वयं के कुल योजना संसाधनों और उनके वास्तविक निष्पादन के अंतर के रूप में किया जाता है।

2. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कुछ कार्यक्रम के संबंध में निष्पादन के मानदंडों के अधीन अनुमोदित फार्मूला में चार उद्देश्य शामिल हैं नामतः (i) जनसंख्या नियंत्रण (ii) असाक्षरता उन्मूलन (iii) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के, समय से पूरा करना और, (iv) भूमि सुधारों में सहायता सफलता।

विवरण–II

राज्यों को केन्द्रीय सहायता का कुल आवंटन 1991–92

राज्य	करोड़ रु० में
क. विशेष श्रेणी राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	230.00
असम	746.45
हिमाचल प्रदेश	255.59
जम्मू व कश्मीर	712.68
मणिपुर	190.95
मेघालय	173.04
मिजोरम	152.00
नागालैंड	163.21
सिक्किम	87.4
त्रिपुरा	193.66
जोड़ : क	2904.99

राज्य	करोड़ रु० में
ख. गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
आंध्र प्रदेश	534.36
बिहार	772.31
गोवा	42.00
गुजरात	229.23
हरियाणा	113.11
कर्नाटक	265.25
केरल	296.00
मध्य प्रदेश	493.30
महाराष्ट्र	375.31
उड़ीसा	340.55
पंजाब	164.57
राजस्थान	385.81
तमिलनाडु	460.17
उत्तर प्रदेश	1081.57
प. बंगाल	379.35
जोड़ : ख	5932.89
सकल जोड़ (क+ख)	8837.88

Census of Industrial Establishments in terms of hired labour

3576. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the census of establishments in non-agricultural sector has recently been completed; and

(b) if so, what is the number of establishments without any hired labourer, establishments with 1 to 5 hired labourers and establishments with 6 to 9 labourers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) A census of all enterprises in agricultural (except crop production and Plantation) and non-agricultural sectors was carried out in 1990 throughout the country except Jammu and Kashmir.